इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दो योजनाओं को मंजूरी

कैबिनेट फैसले

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पीएम-ई ड्राइव स्कीम को मंजूरी दे दी। बैठक में 14,335 करोड़ की दो योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं के माध्यम से दो-तीन पहिया वाहन, एंबुलेंस (हाइब्रिड) और ट्रकों को बढ़ावा दिया जाएगा।

कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 10,900 करोड़ रुपये की ई-ड्राइव स्कीम, 'फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रो एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स' (फेम) का स्थान लेगी। फेम-1 और 2 की सफलता के बाद इस नई स्कीम को लाया जा रहा। फेम में करीब 16 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़कों पर उतारने में मदद मिली। उधर, पीएम-ई बस के लिए 3435 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। चार्जिंग स्टेशन तैयार करने पर भी ध्यान रहेगा। देशभर में 88,500 चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 100 फीसदी सहयोग दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज-चार के तहत 62,500 किमी से अधिक सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई। जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसम की घटनाओं से निपटने और मौसम पूर्वानुमानों को ज्यादा सटीक बनाने के लिए मौसम मिशन को मंजूरी दे दी। दो वर्षों के इस मिशन के लिए दो हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

सार्वजनिक परिवहन में हरित हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो : मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए हरित हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रीत करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन में भी इसका उपयोग होना चाहिए। मोदी ने एक वीडियो संदेश के जरिये ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया-2024 पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक साझेदारी की जरूरत बताई, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी, लागत में कमी और बुनियादी ढांचे का तेज निर्माण संभव हो सके।